Q.1) ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जर्मनी ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया।
2. यह विकासशील देशों में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने की एक व्यवस्था है।
3. यह कार्बन उत्सर्जन क्रेडिट ट्रेडिंग का हिस्सा है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

a) केवल एक
b) केवल दो
c) सभी तीन
d) कोई नहीं

Q.1) Solution (d)

स्पष्टीकरण:

- भारत ने दुबई (यूएई) में COP28 में एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की, **भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रीन क्रेडिट पहल कार्बन क्रेडिट की व्यावसायिक प्रकृति से बेहतर है। (इसलिए कथन 1 गलत है)**
- ग्रीन क्रेडिट पहल को **जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में, स्वैच्छिक ग्रह-समर्थक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में संकल्पित किया गया है।**
- यह **प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को फिर से जीवंत और पुनर्जीवित करने के लिए बंजर/अपघटित भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट के मुद्दे की कल्पना करता है,** जबकि **कार्बन ट्रेडिंग, जिसे कार्बन उत्सर्जन व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, क्रेडिट खरीदने और बेचने के लिए बाज़ार का उपयोग है। जो कंपनियों या अन्य पक्षों को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। (इसलिए कथन 2 और 3 गलत हैं)**
- कार्यक्रम के दौरान एक वेब प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में काम करेगा।
- इसका उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट जैसे कार्यक्रमों/तंत्रों के माध्यम से पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक सहयोग, सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है।

Q.2) लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी?

1. लखनऊ समझौता
2. चंपारण सत्याग्रह
3. रौलट एक्ट
4. जलियांवाला बाग हत्याकांड
5. असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरूआत

6. चौरी चौरा कांड
7. असहयोग आंदोलन को वापस लेना

उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से कितने सही हैं/हैं?

a) 1, 2, 3, 6 और 7
b) 1, 3, 4, 5 और 7
c) 1, 2, 3, 4, और 5
d) 1,2, 3, 4, 5, 6 और 7

Q.2) Solution (c)

स्पष्टीकरण:

लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल में घटित घटनाएँ (1916-1921)

- लखनऊ समझौता (1916)
- चंपारण सत्याग्रह (1917)
- रौलेट एक्ट (1919)
- जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919)
- असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरूआत (1920)
- मोंटेग्यू की अगस्त घोषणा (1917)
- भारत सरकार अधिनियम (1919)

Q.3) आधुनिक भारत के संदर्भ में 'दुबाशेस (Dubashes)' शब्द का सही अर्थ पहचानें:

a) ये वे भारतीय थे जो दो भाषाएं बोल सकते थे - स्थानीय भाषा और अंग्रेजी।
b) ये वे भारतीय थे जो गिरमिट अधिनियम के लागू होने के बाद विदेश चले गए थे
c) ये वे ब्रिटिश नागरिक थे जो भारत में बस गए थे और कभी ब्रिटेन वापस नहीं गए।
d) ये वे पुर्तगाली थे जिन्हें कालीकट में उतरने पर एक विशिष्ट अवधि दी गई थी

Q.3) Solution (a)

स्पष्टीकरण:

- मद्रास का विकास आस-पास के असंख्य गांवों को शामिल करके और विभिन्न समुदायों के लिए अवसर और स्थान बनाकर हुआ। कई अलग-अलग समुदाय कई आर्थिक कार्य करते हुए मद्रास में आकर बस गए। **दुबाशे भारतीय थे जो दो भाषाएँ बोल सकते थे -जैसे स्थानीय भाषा और अंग्रेजी।**
- **उन्होंने एजेंटों और व्यापारियों के रूप में काम किया, भारतीय समाज और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया।** उन्होंने धन अर्जित करने के लिए सरकार में अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का उपयोग किया। समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति उनके धर्मार्थ कार्यों और ब्लैक टाउन में मंदिरों के संरक्षण द्वारा स्थापित की गई थी।

Q.4) "व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक कि उनके कार्यों से दूसरों को नुकसान न पहुंचे"
निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत में उपर्युक्त 'हानि सिद्धांत (Harm Principle)' की व्याख्या की?

a) जॉन रॉल्स
b) जेरेमी बेन्थम
c) जॉन स्टुअर्ट मिल
d) अरस्तू

Q.4) Solution (c)

स्पष्टीकरण:

जेएस मिल (जॉन स्टुअर्ट मिल) द्वारा प्रस्तावित हानि सिद्धांत में कहा गया है कि व्यक्तियों को तब तक अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि उनके कार्यों से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। मिल के अनुसार, किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र उचित कारण दूसरों को नुकसान से बचाना है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार है जब तक कि उनके कार्य दूसरों की भलाई या अधिकारों का उल्लंघन न करें। मिल का मानना था कि समाज को व्यक्तियों पर अपनी नैतिक मान्यताओं या निर्णयों को थोपने से बचना चाहिए जब तक कि दूसरों को कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष नुकसान न हो। हानि सिद्धांत मिल के उदारवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दर्शन में एक केंद्रीय अवधारणा है।

Q.5) जब किसी देश की सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सड़क, पुल, बिजली संयंत्र आदि) पर अपना खर्च काफी बढ़ा देती है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है?

a) यदि व्यय के अनुरूप राजस्व में वृद्धि नहीं की गई तो देश का समग्र ऋण स्तर बढ़ सकता है।
b) बेरोजगारी का स्तर गिर सकता है और कुछ वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो सकता है।
c) सरकारी उधारी बढ़ने के परिणामस्वरूप ब्याज दरें घट सकती हैं।
d) सरकारी खर्च बढ़ने से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भारी कमी आ सकती है।

Q.5) Solution (a)

स्पष्टीकरण:

- विकल्प ए) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, जो सकारात्मक परिणाम हैं। हालाँकि, यदि यह खर्च सरकारी राजस्व (जैसे कर, शुल्क या अन्य स्रोतों से) में वृद्धि से ऑफसेट नहीं होता है, तो सरकार को इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अधिक धन उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। इस बढ़ी हुई उधारी से देश के समग्र ऋण स्तर में वृद्धि हो सकती है। यह ऐसी राजकोषीय नीतियों का प्रत्यक्ष वित्तीय निहितार्थ है जब राजस्व वृद्धि के अनुरूप संतुलित नहीं किया जाता है।
- विकल्प बी) हालांकि यह सच है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से रोजगार सृजन हो सकता है और बेरोजगारी में कमी आ सकती है, यह कथन कि बेरोजगारी "पूरी तरह से समाप्त हो सकती है" अत्यधिक आशावादी है और यथार्थवादी नहीं है। बेरोजगारी कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिनमें आर्थिक स्थिति, तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक बाजार के रुझान शामिल हैं। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि एक भी सरकारी कार्रवाई, जैसे कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना, बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म कर देगी।
- विकल्प c) यह सुझाव कि सरकारी उधारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज दरें गिर सकती हैं, वित्तीय बाजारों में आम तौर पर होने वाली बातों के विपरीत है। जब सरकार अधिक उधार लेती है, तो इससे ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ जाती है, जिससे वास्तव में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। उच्च ब्याज दरें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ऋणदाता ऋण की बढ़ी हुई मांग और उधार देने के कथित उच्च जोखिम के लिए अधिक मुआवजे की मांग करते हैं।
- विकल्प डी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर बढ़े हुए सरकारी खर्च का प्रभाव सीधा नहीं है और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि यह संभव है कि बढ़ा हुआ सरकारी ऋण कुछ निवेशकों को चिंतित कर सकता है, बेहतर बुनियादी ढाँचा भी कारोबारी माहौल में सुधार करके किसी देश को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है। इसलिए, यह दावा करना सही नहीं है कि बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में वृद्धि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में एफडीआई में "भारी कमी" होगी। **(इसलिए विकल्प ए सही है)**